



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 108 ]  
No. 108]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 2001/चैत्र 26, 1923  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 2001/CHAITRA 26, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2001

अंतिम जांच परिणाम

**विषय :** यूरोपीय संघ से सोडियम फ़ैरोसाइनाइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच—अंतिम जांच परिणाम

23/1/2000-डीजीएडी.— 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसके सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए,

क. कार्य पद्धति

निम्नलिखित कार्य पद्धति अपनाई गई है -

( i ) मै0 साइनाइड्स एण्ड कैमिकल्स कंपनी, मुंबई द्वारा दायर याचिका के आधार पर ई यू क्षेत्र (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से सोडियम फ़ैरोसाइनाइड (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के भारत में हुए आयातों के खिलाफ दिनांक 11.6.2000 की अधिसूचना संख्या 23.1.2000-डीजीएडी के द्वारा जांच शुरू की गई थी ।

( ii ) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 2.1.2001 की अधिसूचना द्वारा यूरोपीय संघ से फ़ैरोसाइनाइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया था तथा हित द्ध पार्टियों से इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचार भिजवाने का अनुरोध किया था ।

( iii ) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिनसे निष्कर्षों के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ;

( iv ) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति यूरोपीय आयोग के नई दिल्ली स्थित शिष्ट-मंडल को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार उपर्युक्त पैरा ( ii ) और ( iii ) में यथानिर्धारित समय सीमा के भीतर भेजने की सलाह दी जाए ;

( v ) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को दिनांक 7.2.2001 को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । उक्त पार्टियों को सलाह दी गई थी कि प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और उनका खंडन यदि कोई हो, प्रस्तुत करें ।

( vi ) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाई थी ;

( vii ) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए जिन तर्कों को अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, उन्हें संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । तथापि, प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों पर, इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है ।

( viii ) उपरोक्त नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के लिए किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों से विधिवत विचार किया गया है ।

( ix ) जांच अवधि (पीओआई) में 1.1.99 से 31.12.99 तक की अवधि शामिल है ।

ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा जांच

2. विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों तथा प्रकटन विवरण में भी चर्चा की गई है । प्रारम्भिक निष्कर्षों तथा प्रकटन विवरण में पहले जिन तथ्यों पर चर्चा नहीं की गई थी और जिन्हें अब प्रकटन विवरण के उत्तर में उठाया गया है, उन पर यहां नीचे संबद्ध पैराग्राफों में उस सीमा तक चर्चा की गई है जहां तक नियमों के अनुसार वे संगत हैं और जहां तक वे इस मामले को प्रभावित करते हैं । संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की गई है, उन पर विचार किया गया है और जहां कहीं उचित पाया गया यहां नीचे संबद्ध पैराग्राफों में उन पर चर्चा की गई है ।

ग. घरेलू उद्योग

3. प्रारंभिक निष्कर्षों में इस बात का उल्लेख किया गया था कि मै0 साइनाइड एण्ड कैमिकल कंपनी, मुम्बई, जो इस जांच में एकमात्र याचिकाकर्ता है, का घरेलू उत्पादन में 80 % से अधिक हिस्सा है और इसलिए यह उपरोक्त नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के निर्णय के बारे में हितबद्ध पक्षों ने कोई विवाद नहीं किया है और इसलिए यह निर्धारित करते हैं कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है ।

घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएं

4. प्रारम्भिक निष्कर्षों में यह उल्लेख किया गया था कि सोडियम फ़ैरोसाइनाइड एक अकार्बनिक रसायन है और इसका विनिर्माण सोडियम साइनाइड से किया जाता है, जिसका फेन्सिसाइन, पिगमेंट्स इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग में फोटोग्राफिक फिक्सिंग एजेंट के उत्पादन के लिए, फल अम्लों की किण्वन प्रक्रिया तथा फार्मास्यूटिकल/रसायन उद्योग इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है । सोडियम फ़ैरोसाइनाइड सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची I के सीमाशुल्क कोड संख्या 2837.20 के अंतर्गत वर्गीकृत है । ई यू से आयात किया जा रहा सोडियम फ़ैरोसाइनाइड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे सोडियम फ़ैरोसाइनाइड से लक्षणों में काफी मिलता जुलता है और इसलिए इन दोनों को उपरोक्त नियम 2(घ) के अनुसार समान वस्तु के रूप

में माना गया है। इस प्रकार सोडियम फ़ैरोसाइनाइड उत्पाद को इस जांच के दायरे के अंतर्गत लिया गया है। चूंकि जांचाधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा कोई तर्क नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में यथा उल्लिखित विवरण को ही जारी रखने का निर्णय लिया, जिसकी इस संबंध में एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

#### ड. पाटन

प्राधिकारी ने 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9(1)(ग) के अनुसरण में सूचना देने के लिए ज्ञात निर्यातकों को अवसर प्रदान किया।

जैसे कि प्रारंभिक निष्कर्षों में उल्लेख किया गया है कि ई यू के विनिर्माताओं और निर्यातकों में से केएल एक मै0 डेगुसा हुल्स द्वारा दिए गए उत्तर को स्वीकार किया गया था और घरेलू और निर्यात कीमत के संबंध में उनके द्वारा दी गई सूचना को तथा उत्तराई प्रभार, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन इत्यादि के लिए समायोजन के बारे में उनके दावे को भी स्वीकार किया गया था। इस तर्क को भी स्वीकार किया गया है कि सामान्य मूल्य की गणना ई यू में उन उपभोक्ताओं की गई बिक्री कीमत पर आधारित होगी जिन्होंने भारत में उपभोक्ताओं को आपूर्ति की मात्रा से अधिक मात्रा में आपूर्ति की थी और तदनुसार उसका परिकलन किया गया।

6. प्रारंभिक निष्कर्षों में यह भी उल्लेख किया गया था कि मै0 डेगुसा हुल्स द्वारा सामान्य मूल्य का आकलन करने के उद्देश्य से ऊपर दिए गए तर्क को स्वीकार करते हुए प्राधिकारी ने ऐसी घरेलू बिक्रियों के सौदों पर ध्यान नहीं देने का निर्णय लिया था जो उत्पादन लागत से कम पर की गई हैं क्योंकि उक्त बिक्रियां पाटनरोधी नियमों के अनुबंध I के अनुच्छेद 2 के अनुसरण में कीमतों के कारण व्यापार के सामान्य कारोबार का हिस्सा नहीं थीं। आगे यह भी पाया गया था कि कुछ उपभोक्ताओं के मामले में प्रति इकाई उत्पादन लागत से कम कीमतों पर आपूर्तियां की गई हैं। आगे, यह भी देखा गया था कि ये आपूर्तियां बड़ी मात्राओं में वर्ष भर की जाती रहीं और इस प्रकार उनमें एक समुचित समयावधि के भीतर सभी लागतों की वसूली की व्यवस्था नहीं है।

7. मै0 डेगुसा हुल्स ने प्रारंभिक निष्कर्षों के उत्तर में दिए गए अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा की गई खरीद की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का उनका अनुरोध इन मामलों में तो स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ऐसी मात्रा की खरीद की जो कि भारतीय क्रेताओं की मात्रा के साथ तुलनीय थी लेकिन प्राधिकारी ने दो घरेलू उपभोक्ताओं को की गई बिक्रियों को इस आधार पर छोड़ दिया है कि इन उपभोक्ताओं को बिक्री उत्पादन लागत से कम कीमत पर की गई थीं और इसलिए वे व्यापार के सामान्य कारोबार का हिस्सा नहीं थीं । आगे यह भी तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ऐसे सौदों को छोड़ नहीं सकता है जो कि उत्पादन लागत से कम कीमत पर किए गए हैं क्योंकि सभी तुलनीय सौदों की भारत और घरेलू कीमत भारत और उत्पादन लागत से अधिक है । परिणामस्वरूप उक्त दोनों घरेलू उपभोक्ताओं को की गई बिक्रियां हालांकि उत्पादन लागत से कम पर की गई हैं तब भी उनमें जांच अवधि के दौरान सभी लागतों की वसूली का प्रावधान है । ऐसा इस तथ्य से उजागर होता है कि जांच अवधि के दौरान भारत और घरेलू वसूली भारत और उत्पादन लागत से अधिक है ।

8. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध I का पैरा 2 निम्नानुसार है:-

" निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान उत्पाद की बिक्रियों को अथवा प्रति इकाई उत्पादन लागत जमा प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागत से कम कीमतों (स्थिर तथा परिवर्ती) पर तीसरे देश को की गई बिक्रियों को कीमत के कारण से सामान्य व्यापार के दौरान की गई बिक्रियां नहीं माना जा सकता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय ऐसी बिक्रियों की अनदेखी कर सकते हैं, यदि यह निर्धारित हो जाता है कि -

( i ) ऐसी बिक्रियां प्रचुर मात्रा में एक समुचित समयावधि (छः माह से कम नहीं) के भीतर की जाती हो अर्थात् जब वस्तु की भारत और बिक्री कीमत प्रति इकाई भारत और उत्पादन लागत से कम हो अथवा जब प्रति इकाई लागत से कम कीमत पर की गई बिक्री की मात्रा विचाराधीन सौदों में बेची गई मात्रा के बीस प्रतिशत से कम न हो, और

( ii ) ऐसी बिक्रियां ऐसी कीमतों पर की गई हों जिनसे एक समुचित समयावधि के भीतर सभी लागतों की वसूली न होती हो । उक्त कीमतों को एक समुचित समयावधि के भीतर लागतों की वसूली कराने वाली कमतें माना जाएगा यदि वे जांच अवधि के लिए प्रति इकाई भारित औसत<sup>लागत</sup> से अधिक हों, चाहे वे बिक्री के समय प्रति इकाई लागत से कम हों ।"

9. ऊपर उल्लिखित पाटनरोधी नियमों के अनुबंध I के पैरा 2 के पठन से यह स्पष्ट है कि जिन बिक्रियों से बिक्री के समय लागत की वसूली नहीं होती है और यदि ऐसी बिक्रियां कुल बिक्रियों के 20 % से अधिक हैं तो इन्हें व्यापार के सामान्य चलन में नहीं हुई बिक्रियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा । अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से उत्पादन लागत से कम कीमत पर की गई ऐसी बिक्रियों को नजरन्दाज करने का निर्णय लिया है जो कुल बिक्री के 20 % से अधिक हैं । इसलिए, प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि मै0 डेगुसा हुल्स द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत का 60 % है और यह वही है जो कि प्रारंभिक निष्कर्षों में निर्धारित किया गया था । इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में निर्धारित किया गया था, प्राधिकारी ने ई यू से हुए सभी निर्यातों के लिए वही पाटन मार्जिन लागू रखने का निर्णय लिया है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का ई यू से कोई अन्य विनिर्माता/निर्यातक नहीं दिखाई देता है ।

#### घ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के तहत जब क्षति के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा ।" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों से कीमतों में अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है, अथवा कीमत वृद्धि में अन्यथा रुकावट आई है जो

कि अन्यथा बढ़ गई होती। इसके अतिरिक्त हो रही क्षति का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री की मात्रा पर पाटित आयातों के प्रभाव की भी जांच की गई है।

11. भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उक्त नियमावली के अनुबंध-II(iv) के अनुसरण में ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हों जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों अर्थात् मांग में कमी, मंदी, संघर्ष का गैर किफायती आकार, कच्चे माल और उपयोगिता के ऊँचे और अकुशल खपत मानदण्ड, अधिक ब्याज भार, कम निर्यात इत्यादि, जो घरेलू उद्योगों को साथ-साथ ही क्षति पहुंचा सकते हैं, की जांच की।

12. प्राधिकारी द्वारा क्षति के ऊपर उल्लिखित सभी मापदंडों की जांच की गई थी और उन पर विचार किया गया था तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रारंभिक निष्कर्ष में यह निर्धारित किया गया था कि सभी संगत कारक संचयी तथा सामूहिक रूप से यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान ई यू से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। यह निर्धारित किया गया था कि जांच अवधि के दौरान समग्र रूप में तथा प्रतिशत रूप में ई यू से हुए संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में हुई वृद्धि भारत में की गई कुल बिक्री में घरेलू उद्योग के हिस्से में आई गिरावट से मेल खाती है। यह भी निर्धारित किया गया था कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यह पाया गया था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय बाजार में पाटित आयातों के कारण कीमत अवूल्यन की स्थिति रही है जिसने घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन लागत की आनुपातिक कीमत पर बेचने से रोका जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से हानि हुई। निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वास्तविक क्षति के समर्थन में घरेलू उद्योग विभिन्न आधार वर्षों को अपनाकर क्षति के मुद्दे को अस्पष्ट कर रहा है। तथापि, जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह तुलना पिछले वर्ष के आंकड़ों के संदर्भ में भी की गई है और न केवल 1996 के संदर्भ में ही, जैसाकि आरोप लगाया गया है। इसलिए, प्राधिकारी क्षति के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि

कि अन्यथा बढ़ गई होती। इसके अतिरिक्त हो रही क्षति का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री की मात्रा पर पाटित आयातों के प्रभाव की भी जांच की गई है।

11. भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उक्त नियमावली के अनुबंध-II(iv) के अनुसरण में ऐसे संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हों जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों अर्थात् मांग में कमी, मंदी, संरुंन का गैर किफायती आकार, कच्चे माल और उपयोगिता के ऊंचे और अकुशल खपत मानदण्ड, अधिक ब्याज भार, कम निर्यात इत्यादि जो घरेलू उद्योगों को साथ-साथ ही क्षति पहुंचा सकते हैं, की जांच की।

12. प्राधिकारी द्वारा क्षति के ऊपर उल्लिखित सभी मापदंडों की जांच की गई थी और उन पर विचार किया गया था तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रारंभिक निष्कर्ष में यह निर्धारित किया गया था कि सभी संगत कारक संचयी तथा सामूहिक रूप से यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योगों को जांच अवधि के दौरान ई यू से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है। यह निर्धारित किया गया था कि जांच अवधि के दौरान समग्र रूप में तथा प्रतिशत रूप में ई यू से हुए संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में हुई वृद्धि भारत में की गई कुल बिक्री में घरेलू उद्योग के हिस्से में आई गिरावट से मेल खाती है। यह भी निर्धारित किया गया था कि घरेलू उद्योगों के क्षमता उपयोग में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यह पाया गया था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय बाजार में पाटित आयातों के कारण कीमत अवूल्यन की स्थिति रही है जिसने घरेलू उद्योगों को अपनी उत्पादन लागत की आनुपातिक कीमत पर बेचने से रोका जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से हानि हुई। निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वास्तविक क्षति के समर्थन में घरेलू उद्योग विभिन्न आधार वर्षों को अपनाकर क्षति के मुद्दे को अस्पष्ट कर रहा है। तथापि, जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह तुलना पिछले वर्ष के आंकड़ों के संदर्भ में भी की गई है और न केवल 1996 के संदर्भ में ही, जैसाकि आरोप लगाया गया है। इसलिए, प्राधिकारी क्षति के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योगों को जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति हुई है।



13. प्रारंभिक निष्कर्षों के पश्चात् अपनी टिप्पणियों में मै. देगुसा हल्स द्वारा यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति और विशेषकर कीमत कटौती और कीमतों में गिरावट चीन से हुए आयातों के कारण हुई है और यूरोपीय संघ से हुए आयातों के कारण नहीं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि देगुसा हल्स ने उस कीमत पर बाजार में प्रवेश किया, जो घरेलू उद्योग द्वारा वसूल की जा रही कीमत से मेल खाती थी और यदि घरेलू उद्योग की कीमत को बराबर करके निर्यातक बाजार हिस्सा प्राप्त कर सका तो इसे क्षति का कारण नहीं कहा जा सकता है।

14. कारणात्मक संबंध के मुद्दे का समाधान प्रारंभिक निष्कर्षों में किया गया है, जहां यह निर्धारण किया जा चुका है कि यूरोपीय संघ से पाटित कीमत पर हुए पाटित आयातों के कारण विशेषकर भारतीय बाजार में प्रचलित कीमत में कटौती की स्थिति के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट यूरोपीय संघ से पाटित आयातों के फलस्वरूप हुई है ऐसा प्रमाणित हो चुका था। निर्यातक के उपर्युक्त इस तर्क पर भी कि घरेलू उद्योग को क्षति चीन से हुए निर्यातों द्वारा हुई है और यूरोपीय संघ से हुए निर्यातों द्वारा नहीं, पर प्रारंभिक निष्कर्षों में विचार किया जा चुका है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में दिए गए कारणात्मक संबंध के निर्धारण को जारी रखने का निर्णय लिया है और इन निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

#### छ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

15. प्राधिकारी दोहराते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से बहाल करना है जो कि देश के सामान्य हित में है।

16. प्राधिकारी दोबारा यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से सोडियम फॉरोसाइनाइड के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हों सकते हैं और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभों को समाप्त किया जा सकेगा। भारतीय उद्योग के ह्रास हो रोका जा सकेगा और इस प्रकार सोडियम फॉरोसाइनाइड के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प

उपलब्ध रहेगा । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से यूरोपीय संघ से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा । उपभोक्ता तब भी आपूर्ति के दो अथवा अधिक स्रोत रख सकते हैं ।

17. घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन की ईष्टतम लागत पर विचार करके भारत में घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध वस्तु की क्षति रहित बिक्री कीमत पर विश्वास किया है ।

18. घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण सभी आवश्यक कारकों जैसे कच्चे माल का उपयोग, उपयोगिता का उपयोग, कैप्टिव उपयोग, उपयोगिता के कैप्टिव सृजन इत्यादि और जांच अवधि के दौरान निवेश तथा क्षमता उपयोग सहित वास्तविक व्यय का उपयुक्त विश्लेषण करके किया गया है । घरेलू उद्योग के एन आई पी का निर्धारण उत्पादन की ईष्टतम लागत पर विचार करके और घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी की उचित प्रसूती पर विचार करके किया गया है । एन आई पी का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने कच्चे माल और उपयोगिता के उत्तम उपभोग-मानदंडों को ध्यान में रखा है और इसलिए ऐसी किसी प्रकार की अक्षमताओं का निराकरण किया है, जिससे इन अक्षमताओं के कारण उद्योग को वित्तीय क्षति हो सकती है ।

#### ज. अन्तिम निष्कर्ष

19. प्राधिकारी उपरोक्त विचार करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि

- (i) यूरोपीय संघ के भूल के सोडियम फ़ैरोसाइनाइड का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया;
- (ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (iii) उक्त क्षति यूरोपीय संघ से हुए आयातों के कारण हुई है ।

20 प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन के बराबर अथवा ऐसे कम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पर विचार किया गया, जिसे यदि लागू किया जाता है, तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। क्षति का निर्धारण करने के लिए आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनियों की क्षति रहित बिक्री कीमत के साथ की गई थी।

21 प्राधिकारी यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क कोड 2837.20 के तहत आने वाले सोडियम फैरोसाइनाइड के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में पहले ही निर्धारित किया गया है पाटनरोधी शुल्क कॉलम 3 में दी गई धनराशि और प्रति मी.टन आयात के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा।

क्षेत्र/देश	उत्पादक/निर्यातक का नाम	राशि (यू एस डॉलर प्रति मी.टन)
1	2	3
यूरोपीय संघ (सभी सदस्य देश)	मै. देगुसा हल्स और सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	1535

22. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, तथा 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्क शामिल होंगे

23. उपोक्त के अधीन प्राधिकारी दिनांक 2.1.2001 के प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

24. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकती है।

एल. बी. सप्तर्चाय, निर्देशक, राजस्व

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2001

**FINAL FINDINGS**

**Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Sodium ferrocyanide from European Union—Final Findings**

**23/1/2000-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

**A. PROCEDURE**

1. The procedure described below has been followed:
  - (i) Based on the petition filed by M/s. Cyanides and Chemicals Company, Mumbai, investigation against imports into India of Sodium ferrocyanide (hereinafter referred to as subject goods) from the territory of EU (hereinafter referred to as subject country) were initiated vide notification of number 23.1.2000-DGAD dated 11.6.2000.
  - (ii) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified preliminary findings vide notification dated 2.1.2001 on anti-dumping

investigation concerning imports of Sodium ferrocyanide from European Union and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

- (iii) The Authority forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days from the date of its publication;
- (iv) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Delegation of European Commission in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (ii) and (iii) above.
- (v) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 7.2.2001. All parties presenting views were requested to file written submissions of their views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;
- (vi) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request;
- (vii) Argument raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the

interested parties subsequently have been appropriately dealt in these findings;

- (viii) In accordance with Rule 16 of the Rules *supra*, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- (ix) The period of investigation (POI) considered is 1.1.99 to 31.12.99.

**B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY**

2. The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paragraphs herein below.

**C. DOMESTIC INDUSTRY**

3. It was mentioned in the preliminary findings that M/s. Cyanide and Chemical Co., Mumbai, who are the only petitioner in this investigation, account for more than eighty percent of the domestic production and therefore constitute domestic industry in accordance with Rule 2(b) *supra*. The Authority notes that there is no argument raised by interested parties on the standing of the petitioners and hence determine that the petitioner represent domestic industry for the purpose of present investigation.

#### **D. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLES**

4. It was mentioned in the preliminary findings that Sodium Ferrocyanide is an Inorganic chemical and is manufactured out of Sodium Cyanide, having application for production of fencycine, pigments, photographic fixing agents in electroplating industry, for fermentation processes of fruits acids and pharmaceutical/chemical industry etc. Sodium Ferrocyanide is classified under custom code 2837.20 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. Sodium Ferrocyanide being imported from EU has characteristics closely resembling to the Sodium Ferrocyanide being produced by the domestic industry and, therefore, the two are considered as like article in accordance with Rule 2(d) *supra*. The product, Sodium Ferrocyanide is, therefore, covered under the scope of this investigation. As there is no argument raised by any interested with regard to product under consideration and like article, the Authority has decided to continue with the same description as given in the preliminary findings which are hereby confirmed in this regard.

#### **E. DUMPING**

5. The Authority provided opportunity to the known exporters to furnish information in accordance with Section 9(1) © of the Custom Tariff Act 1975, as amended in 1995, cited above. As mentioned in the preliminary finding, the response given by M/s. Degussa Huls, one of the manufacturers and exporters from EU was accepted and the information given by them regarding the domestic and export prices as well as their claim for adjustments on account of landing charges, ocean freight, marine insurance, commission, etc., was also accepted. The argument that the calculation of normal value shall be based on the sale price to those customers in EU who have supplied quantities in excess of the

volume supplied to the customers in India, was also accepted and calculations made accordingly.

6. It was also mentioned the preliminary findings that while accepting the arguments by M/s. Degussa Huls above, for the purpose of calculation of normal value, the Authority had decided to ignore the transactions of the domestic sales which are below cost of production as not being in the ordinary course of trade by reason of prices in terms of paragraph 2 of Annexure I of Anti Dumping Rules. It was further observed that in the case of some customers supplies have been made at prices below the cost of production per unit. Further, it was observed that these supplies have been made in substantial quantities throughout the year and hence do not provide for recovery of all costs within a reasonable period of time.

7. In their submissions made in response to the preliminary findings M/s. Degussa Huls have argued that while accepting their request to determine normal value based on price to domestic customers who purchased quantities that were comparable to that of Indian buyers, the Authority has omitted the sales to two domestic customers on the ground that the price to these customers was below the cost of production and hence were not in the ordinary course of trade. It has further been contended that the Authority is precluded from excluding such transactions which are below the cost of production because the weighted average domestic price of all comparable transactions is higher than the weighted average cost of production. Consequently, the sales to the two domestic customers, though below the cost of production, provide for the recovery of all the costs during the period of investigation. This is borne out by the fact that the weighted average domestic realisation is higher than the weighted average cost of production of the Pol.

8. Para 2 of Annexure I of Anti Dumping Rules reads as follows:-



“ Sales of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, selling and general costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price. The designated authority may disregard these sales, in determining normal value, provided it has determined that -

- (i) such sales are made within a reasonable period of time (not less than six months) in substantial quantities, i.e. when the weighted average selling price of the article is below the weighted average per unit costs or when the volume of the sales below per unit costs represents not less than twenty per cent of the volume sold in transactions under consideration, and
- (ii) such sales are at prices which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time. The said prices will be considered to provide for recovery of costs within a reasonable period of time if they are above weighted average per unit costs for the period of investigation, even though they might have been below per unit costs at the time of sale.”

9. It is clear from the reading of para 2 of Annexure I of Anti Dumping Rules cited above, that sales which do not provide for recovery of cost at the time of sale and if these sales are more than 20% of the total sales then these are to be accepted as not being in the ordinary course of trade. Therefore, the Authority had decided to ignore the sales below cost of production which are more than 20% of the total sales for the purpose of arriving the normal value. The Authority, therefore, reiterates that the dumping margin in respect of exports made by M/s. Degussa Huls comes to 60% of the

112261/2001—3

export price which is the same as what was determined in the preliminary findings. Also, as done in the preliminary findings, the Authority has decided to continue to use the same dumping margin for all the exports from EU as there does not seem to be any other manufacturer/exporter from the EU of the product under consideration.

#### **F. INJURY AND CAUSAL LINK**

10. Under Rule 11 *supra*, annexure II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, "*.....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.....*" In considering the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred. Also the effect of dumped imports on the volume of sales by the domestic industry has been looked into while determining injury being caused.

11. For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc., in accordance with Annexure II (iv) of the Rules *supra*. The Authority has also examined factors other than dumped imports viz., demand contraction, recession, uneconomical plant size, high and inefficient consumption norms of raw materials and utilities, high interest burden, distress exports etc., which might be injuring the domestic industry at the same time.

12. All the parameters of injury mentioned above, were examined and considered by the Authority and on the basis of the evidence available it was determined in the preliminary finding that all the relevant factors, cumulatively and collectively establish that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation caused by dumped imports from EU. It was determined that the increase in volume of imports in absolute as well as percentage terms of subject goods from EU is matched by fall in the share of domestic industry in total sales in India during the period of investigation. It was further determined that there has been a significant fall in the capacity utilisation of the domestic industry. It was observed that most significant effect has been the situation of price suppression caused by dumped imports in the Indian market which prevented the domestic industry to sell at prices not commensurate with its cost of production resulting in losses from the sale of the subject goods in the domestic market. It has been argued by the exporter that the domestic industry is obfuscating the issue of injury by adopting different base years to support material injury. However, as is clear from the figures given in the preliminary finding the comparison has been with reference to the previous year data also and not with reference to 1996 only as alleged. The Authority, therefore, confirms the preliminary findings with respect to injury and determines that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation.

13. In their comments subsequent to the preliminary findings it has been argued by M/s. Degussa Huls that the injury caused to the domestic industry and especially the price suppression and price depression have been caused by imports from China and not by imports from EU. It has further been argued that Degussa Huls entered the market at a price which was matching the price being charged by the domestic industry and if by matching the price of the domestic industry the exporter was able to obtain a market share, that cannot be said to be causing injury.

14. The issue of causal link has been addressed in the preliminary finding where it has been determined that the dumped imports at dumped price from EU have caused injury to the domestic industry especially because of situation of price undercutting prevailing in the Indian market and fall in the sales volume of domestic industry was established to be a result of dumped imports from the EU. The above mentioned contention of the exporter that injury to the domestic industry has been caused by Chinese exports and not by the exports from EU has also been discussed in the preliminary finding. The Authority has decided to continue with the determination of causal link given in preliminary finding and confirm these findings.

#### **G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**

15. The Authority reiterates that the purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

16. The Authority again recognises that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using Sodium Ferrocyanide and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of Sodium Ferrocyanide. The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from EU in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

17. To ascertain the extent of anti dumping duty necessary to remove the injury to the domestic industry, the Authority has relied upon non injurious selling price of subject goods in India for the domestic industry by considering the optimum cost of production for the domestic industry.

18. The non injurious price for the domestic industry has been determined by making appropriate analysis of all relevant factors like usage of raw material, usage of utilities, captive consumption, captive generation of utilities etc., and the actual expenses during the period of investigations including the investments and capacity utilisation. The NIP of domestic industry has been determined by considering the optimum cost of production and considering the reasonable return on the capital employed by the domestic industry. While determining NIP, the Authority has taken into account the best consumption norms of raw materials and utilities and has, thereby addressed any inefficiencies which might lead to financial injury to the industry on account of the inefficiencies.

#### **H. FINAL FINDINGS**

19. After considering the foregoing the Authority concludes that -

- (i) Sodium Ferrocyanide of EU origin has been exported to India below its normal value;
- (ii) the Indian industry has suffered material injury;
- (iii) the injury has been caused by the imports from EU.

20. The Authority proposes to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed price of imports is proposed to be compared with the non injurious selling price of the petitioner companies determined for the period of investigation.

21. The Authority recommends imposition of definitive anti dumping duty on all imports of sodium ferrocyanide falling

under Customs Code 2837.20 originating in or exported from European Union. As already determined in the preliminary finding, the anti dumping duty shall continue to be the difference between the amount mentioned in column 3 and landed value of import per MT.

<b><i>Territory/Coun try</i></b>  <b><i>(1)</i></b>	<b><i>Name of Producer/Exporter</i></b>  <b><i>(2)</i></b>	<b><i>Amoun t in US\$ per MT</i></b>  <b><i>(3)</i></b>
European Union (all member- countries)	M/s. Degussa Huls and all other producers/exporters	1535

22. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

23. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 2.1.2001.

24. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, *supra*.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority